

आंधी से गिरा मड़हा, मलबे में लाखों की लागत से नगरीय विस्तार, सुंदरीकरण के लिए बस स्टैंड हटाना आवश्यक

मीरजापुर। आंधी-तफान के साथ हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन नुकसान भी हुआ। कई कच्चे मकान ढ

गया तो कभी भी अग्रिय घटना घट सकती है। जाम लगाने की जानकारी पर कस्ता चौंकी प्रशासी धैर्य कुमार मयफोर्स और नार पंचायत के गए तो कई पेड़ धराइ हो गए।

कई लोग घायल भी हुए। कछु क्षेत्र के गर्व थाना में स्थित साई मंदिर के पास स्थित एक मड़हा का जर्जर दी बार समवार को तेज आंधी के चलते गिर गया। इसके मलबे में 20 वर्षीय जातील व 40 वर्षीय मोहम्मद जाहीद डब गए। आसपास के लोगों

ने काफी मशक्कत के दोनों को मलबे से बार निकालकर अस्पताल ले गए। इसके बाद आंधीशित खजानों ने सारा मलगा वृक्षों ने राहत की सीधासीली हालिया दिया। आरपण लगाया कि मंदिर की तरफ से कुछ लोग घर का मरम्मत नहीं करने देते हैं, जिसके बजे से आज यह हादसा हुआ है। अगर मरम्मत नहीं कराया

लिपिक दूधनाथ मौके पर पहुंच गए और सड़क पर फेंके गए मलबे को साइक्लोक बुकाकर हवाया, तब जाकर लोगों ने राहत की सीधासीली हालिया दिया। आरपण लगाया कि मंदिर की तरफ से कुछ लोग घर का मरम्मत नहीं करने देते हैं, जिसके बजे से आज यह हादसा हुआ है। अगर मरम्मत नहीं कराया लोगों

ने निवासी 70 वर्षीय रामकीर्णी पतनी मड़हा पाल अपनी नन्द 72 वर्षीय तरीसे पतनी लोठ निवासी सोनादा का साथ आंधी-पानी के दौरान कर्चे मकान की दीवार गिरने से दो अंधेरे लोग रुप से घायल हो गई। मंगलवार सुबह स्वजन घायलों को उपचार के लिए एंबुलेंस से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हलिया लेकर गया। बैंधा गांव

की प्रक्रिया प्रशासन द्वारा पूर्ण नहीं करायी गई। इससे किसान व सब्जी लगाकर बैचने की विश्व है। वही जाम की समस्या उत्पन्न होती है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्राम पंचायत टौंग में सब्जी मटी का निर्माण हो रहा था तब उसे देखकर यही लगा था कि इसका एक स्थान कच्चे मकान का दीवार भर-भराकर आचानक गिर पड़ा। इससे दोनों घायल हो गई।

प्रश्न पहर : सुकन्या समृद्धि योजना से समृद्ध होगा बेटियों का भविष्य

आजमगढ़। सुकन्या समृद्धि योजना से बेटियों का भविष्य समृद्ध होगा। खाता खोलने के लिए बेटी का जन्म प्रमाण पत्र और माता पा पिता का आधार कार्ड, वैन कार्ड की स्प्रिमापाइट छाया प्रति दीनी होती है। बेटी की उम्र 10 वर्ष तक होनी

लगेगा। खाता कहां खुल सकता है जबवाब : खाता मात्र 10 रुपये में डाकघर से प्राप्त हो सकता है जबवाब : अधिकृत डाकघरों में गंगोत्री से प्राप्त गंगा जल 250 एमएल 30 रुपये में उपलब्ध है। सवाल : डाकघर में पासपोर्ट सेवा उपलब्ध है। इसके बाद भी खोला जा सकता है। खाता खोलने के लिए काफी अधिकृत डाकघरों में गंगोत्री से प्राप्त गंगा जल 250 एमएल 30 रुपये में उपलब्ध है। सवाल : मेरी एक बेटी का सुकन्या खाता चल रहा है। इसके बाद भी यही तो क्या इनका भी योजना का खाता खोला जा सकता है जबवाब : हाँ, एक बेटी के बाद दो जुड़वां बेटियों का भी खाता खोला जा सकता है। सवाल : डाक जीवन बीमा व ग्रामीण डाक जीवन बीमा की अधिकतम सीमा क्या है जबवाब : डाक जीवन बीमा की अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये और ग्रामीण डाक बीमा की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये है। सवाल : मेरे बेटे की उम्र 10 वर्ष है, क्या उसका पीपीएक खाता खोला जा सकता है जबवाब : हाँ, यह खाता संरक्षक की तरफ से खोला जाएगा। इसमें क्या-क्या अभिलेख

चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र के लिए अस्पताल से जारी प्रमाण पत्र, ग्राम प्रदान से जारी प्रमाण पत्र, स्कूल से जारी पहचान पत्र से खाता खोला जा सकता है। यह खाता 250 रुपये से खोला जा सकता है। यह जानकारी प्रवर डाक अंधीक्षक योगेंद्र मोर्ये ने मंगलवार को दीनक जागरण के 'प्रश्न पहर' में लोगों के सवालों के जवाब दी है। सवाल : मुझे आइपीपीबी खाता खोला जा सकता है जबवाब : हाँ, यह खाता

कोड दिया जाता है। समय-समय पर कैप लगाकर भी खाता खोला जा रहा है। सवाल : मेरी एक बेटी का सुकन्या खाता चल रहा है। इसके बाद भी यही तो क्या इनका भी योजना का खाता खोला जा सकता है जबवाब : हाँ, एक बेटी के बाद दो जुड़वां बेटियों का भी खाता खोला जा सकता है। सवाल : डाक जीवन बीमा व ग्रामीण डाक जीवन बीमा की अधिकतम सीमा क्या है जबवाब : डाक जीवन बीमा की अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये और ग्रामीण डाक बीमा की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये है। सवाल : मेरे बेटे की उम्र 10 वर्ष है, क्या उसका पीपीएक खाता खोला जा सकता है जबवाब : हाँ, यह खाता

संरक्षक की तरफ से खोला जाएगा। इसमें क्या-क्या अभिलेख

चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र के लिए अस्पताल से जारी प्रमाण पत्र, ग्राम प्रदान से जारी प्रमाण पत्र, स्कूल से जारी पहचान पत्र से खाता खोला जा सकता है। यह जानकारी प्रवर डाक अंधीक्षक योगेंद्र मोर्ये ने मंगलवार को दीनक जागरण के 'प्रश्न पहर' में लोगों के सवालों के जवाब दी है। सवाल : मुझे आइपीपीबी खाता खोला जा सकता है जबवाब : हाँ, यह खाता

कोड दिया जाता है। समय-समय पर कैप लगाकर भी खाता खोला जा रहा है। सवाल : मेरी एक बेटी का सुकन्या खाता चल रहा है। इसके बाद भी यही तो क्या इनका भी योजना का खाता खोला जा सकता है जबवाब : हाँ, एक बेटी के बाद दो जुड़वां बेटियों का भी खाता खोला जा सकता है। सवाल : डाक जीवन बीमा व ग्रामीण डाक जीवन बीमा की अधिकतम सीमा क्या है जबवाब : डाक जीवन बीमा की अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये और ग्रामीण डाक बीमा की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये है। सवाल : मेरे बेटे की उम्र 10 वर्ष है, क्या उसका पीपीएक खाता खोला जा सकता है जबवाब : हाँ, यह खाता

संरक्षक की तरफ से खोला जाएगा। इसमें क्या-क्या अभिलेख

चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र के लिए अस्पताल से जारी प्रमाण पत्र, ग्राम प्रदान से जारी प्रमाण पत्र, स्कूल से जारी पहचान पत्र से खाता खोला जा सकता है। यह जानकारी प्रवर डाक अंधीक्षक योगेंद्र मोर्ये ने मंगलवार को दीनक जागरण के 'प्रश्न पहर' में लोगों के सवालों के जवाब दी है। सवाल : मुझे आइपीपीबी खाता खोला जा सकता है जबवाब : हाँ, यह खाता

कोड दिया जाता है। समय-समय पर कैप लगाकर भी खाता खोला जा रहा है। सवाल : मेरी एक बेटी का सुकन्या खाता चल रहा है। इसके बाद भी यही तो क्या इनका भी योजना का खाता खोला जा सकता है जबवाब : हाँ, एक बेटी के बाद दो जुड़वां बेटियों का भी खाता खोला जा सकता है। सवाल : डाक जीवन बीमा व ग्रामीण डाक जीवन बीमा की अधिकतम सीमा क्या है जबवाब : डाक जीवन बीमा की अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये और ग्रामीण डाक बीमा की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये है। सवाल : मेरे बेटे की उम्र 10 वर्ष है, क्या उसका पीपीएक खाता खोला जा सकता है जबवाब : हाँ, यह खाता

संरक्षक की तरफ से खोला जाएगा। इसमें क्या-क्या अभिलेख

चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र के लिए अस्पताल से जारी प्रमाण पत्र, ग्राम प्रदान से जारी प्रमाण पत्र, स्कूल से जारी पहचान पत्र से खाता खोला जा सकता है। यह जानकारी प्रवर डाक अंधीक्षक योगेंद्र मोर्ये ने मंगलवार को दीनक जागरण के 'प्रश्न पहर' में लोगों के सवालों के जवाब दी है। सवाल : मुझे आइपीपीबी खाता खोला जा सकता है जबवाब : हाँ, यह खाता

कोड दिया जाता है। समय-समय पर कैप लगाकर भी खाता खोला जा रहा है। सवाल : मेरी एक बेटी का सुकन्या खाता चल रहा है। इसके बाद भी यही तो क्या इनका भी योजना का खाता खोला जा सकता है जबवाब : हाँ, एक बेटी के बाद दो जुड़वां बेटियों का भी खाता खोला जा सकता है। सवाल : डाक जीवन बीमा व ग्रामीण डाक जीवन बीमा की अधिकतम सीमा क्या है जबवाब : डाक जीवन बीमा की अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये और ग्रामीण डाक बीमा की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये है। सवाल : मेरे बेटे की उम्र 10 वर्ष है, क्या उसका पीपीएक खाता खोला जा सकता है जबवाब : हाँ, यह खाता

संरक्षक की तरफ से खोला जाएगा। इसमें क्या-क्या अभिलेख

चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र के लिए अस्पताल से जारी प्रमाण पत्र, ग्राम प्रदान से जारी प्रमाण पत्र, स्कूल से जारी पहचान पत्र से खाता खोला जा सकता है। यह जानकारी प्रवर डाक अंधीक्षक योगेंद्र मोर्ये ने मंगलवार को दीनक जागरण के 'प्रश्न पहर' में लोगों के सवालों के जवाब दी है। सवाल : मुझे आइपीपीबी खाता खोला जा सकता है जबवाब : हाँ, यह खाता

कोड दिया जाता है। समय-समय पर कैप लगाकर भी खाता खोला जा रहा है। सवाल : मेरी एक बेटी का सुकन्या खाता चल रहा है। इसके बाद भी यही तो क्या इनका भी योजना का खाता खोला जा सकता है जबवाब : हाँ, एक बेटी के बाद दो जुड़वां बेटियों का भी खाता खोला जा सकता है। सवाल : डाक जीवन बीमा व ग्रामीण डाक जीवन बीमा की अधिकतम सीमा क्या है जबवाब : डाक जीवन बीमा की अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये और ग्रामीण डाक बीमा की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये है। सवाल : मेरे बेटे की उम्र 10 वर्ष है, क्या उसका पीपीएक खाता खोला जा सकता है जबवाब : हाँ, यह खाता

स

सम्पादकीय

किसी सैन्य घटक के बिना
क्वाड न तो हिंद-प्रशांत क्षेत्र
में शांति कायम करने में
समर्थ हो सकेगा और न ही
चीन की काट कर पाएगा

क्योंकि यहां में आयोजित क्वाड देशों का तीसरा शिखर सम्मेलन विश्व व्यवस्था के निर्धारण में हिंद-प्रशांत की केंद्रीय भूमिका की पुष्टि का प्रतीक है। इस समय रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पर्वी यूरोप पर टिका हुआ है। ऐसी एशिया में क्वाड के चारों देशों भारत, अमेरिका, जापान और आस्ट्रेलिया के राष्ट्र प्रमुखों का जापान में बैठक करना और एशिया के भविष्य की रूपरेखा पर रणनीति बनाना यही संकेत करता है कि एशिया में शक्ति संतुलन ही अंततः वैश्विक भू-राजनीति एवं भू-अर्थनीति में निर्णायक सिद्ध होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति यही रही कि दुनिया के तीन प्रमुख क्षेत्रों में किसी भी प्रतिद्वंद्वी को हावी नहीं होने देना है। ये प्रमुख क्षेत्र रहे यूरोप, पश्चिम एशिया और पूर्वी एशिया। इसके पाछे अमेरिका का यह सोच रहा कि इनमें से कहीं भी अगर शक्ति संतुलन अमेरिका के विपरीत गया तो उसके लिए वैश्विक महाशक्ति बने रह पाना संभव नहीं होगा। बाइडन प्रशासन द्वारा 2021 में जारी 'राष्ट्रीय सुरक्षा सामरिक मार्गदर्शन' में यही दोहराया गया है। उससे यही स्पष्ट होता है कि अमेरिकी सुरक्षा के लिए दुनिया के प्रमुख क्षेत्रों पर विराधियों का आधिपत्य होने से रोकना अनिवार्य है। पश्चिम एशिया और यूरोप में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे सके। ईरान और रूस जैसे देश अमेरिका को परेशान करते आए हैं, लेकिन उनमें उतना आर्थिक विवरण नहीं है कि वे इस विश्व व्यवस्था के निर्धारण में हिंद-प्रशांत की केंद्रीय भूमिका की पुष्टि का प्रतीक है। इसे हिंद-प्रशांत आर्थिक ढांचा' नाम दिया गया है। इसमें अमेरिका, भारत, आस्ट्रेलिया, ब्रूनेई, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाइलैंड और वियतनाम शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस फ्रेमवर्क के उद्घाटन पर उपस्थित होना दर्शाता है कि भारत इसके सामरिक लाभ को समझता है। आपूर्ति श्रृंखला को लंगीला बनाना, 5जी तकनीक का सुरक्षित एवं भरोसे मंद विकास, उच्च गुणवत्ता वाला बुनियादी ढांचा और स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन आदि इस गठजोड़ के प्रमुख उद्देश्य बताए जा रहे हैं। सुलिवन ने डके की चोट पर कहा कि इसकी धमक बीजिंग तक सुनाई पड़ेगी। इसमें चीन की बैल एंड रोड परियोजना को टक्कर देने की पूरी संभावना है। यह क्वाड प्लूस के रूप में उसका औपचारिक विस्तार तो नहीं, लिंग्टु अनैपचारिक तरीके से आकार लेने वाले इस ढांचे में चीन की काट करने की क्षमता जरूर है। क्वाड के चार मूल सदस्य ही हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बहुआयामी क्षमता रखते हैं। ऐसे में उहें स्वाभाविक रूप से इस इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का साझा नेतृत्व करना होगा। ये चारों देश पहले ही इन्फ्रास्ट्रक्चर, वैक्सीन, आपूर्ति श्रृंखला, सामरिक साझेदारी और सेमीकंडक्टर आदि क्षेत्रों में समझौते कर चुके हैं और उनमें से कुछ पर काम भी शुरू हो चुका है। ऐसे में साझेदारी के इस दायरे को बढ़ाना और नए सहयोगियों को उसमें जोड़ा ही बुद्धिमत्ता होगी। अमूमन यही

एवं सन्य बल नहा, जिससे व
अमेरिका को मात दे सकें। केवल
पूर्वी एशिया में स्थित चीन ही
अमेरिका को चुनौती देने में सक्षम
दिखाई पड़ता है और वह इसके
कमर भी कस रहा है। अमेरिका
भी इससे भलीभांति अवगत है।
यही कारण है कि अमेरिकी
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक
सुलिवन ने कहा कि हिंद-प्रशांत
क्षेत्र ही इक्कीसवीं सदी के भविष्य
को परिभाषित करेगा और
अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन इस
मामले में अमेरिकी नेतृत्व एवं
भागीदारी को लेकर प्रतिबद्ध है।
उल्लेखनीय है कि क्वाड के साथ
माना जाता है कि जन
अंतरराष्ट्रीय आर्थिक ढांचों में
अधिक हितधारक होते हैं, वहाँ
समन्वय, सहमति बनाकर
अपेक्षित कार्य को शीघ्रता से
संपादित करना सभव नहीं होता।
इसलिए इस फ्रेमवर्क में विभिन्न
पक्षों को देखते हुए उसकी
कार्यसंस्कृति को बेतर बनाने के
उपाय करने होंगे। बाइडन प्रशासन
कहता आ रहा है कि उसका लक्ष्य
यह सिद्ध करना है कि 'लोकतात्रिक देश वादों और
अपेक्षाओं पर खरे उत्तर सकते हैं
और तानाशाही वाले देशों से बेहतर
प्रदर्शन दिखा सकते हैं।'

**कल्याणकारी योजनाओं से
दिव्यांगजनों को सशक्ति
बना रही है प्रदेश सरकार**

भूजल संरक्षण की राह दिखाता पंजाब, धन की
खेती में पानी की खपत बचाने की ठोस पहल

पंजाब में धान की फसल के लिए वर्षी से पानी के अंधार्घुंघ दोहन के चलते रसातल में जा पहुंचे भूजल की गंभीर समस्या से निपटने के लिए भारत मान सरकार ने जो पहल की है, वह उम्मीद की नई रोशनी लेकर आई है। पंजाब की नई सरकार ने हाल में धान की बुआई के लिए 1,500 रुपये प्रति हैक्टेयर प्रोत्साहन राशि देने की प्रतिशत से अधिक का सुधार होता है। स्पष्ट है कि यह तकनीक जल स्तर में आती खतरनाक गिरावट को काफी हद तक रोक सकती है। धान की परंपरागत रोपाई विधि के तहत किसान नर्सरी में धान के बीजों से पौधों को उगाता है। बाद में इन पौधों को लगभग एक महीने बाद पानी वाले खेत में लगाता है। रोपाई के बाद पहले तीन-चार हफ्तों तक

A photograph showing a man in a red long-sleeved shirt and grey trousers standing in a dry, brown field. He is facing away from the camera towards a yellow agricultural machine, possibly a harvester or planter, which is positioned on the right side of the frame. The machine has green and black components attached to its front. The background shows a hazy, mountainous landscape under a clear sky.

स्तर इसलिए नीचे जाता गया, क्योंकि यहाँ धान की खेती पारंपरिक विधि से ही की जाती रही, जिसमें पानी की अधिक खपत होती है। धान की सीधी बुआई वाली डीएसआर तकनीक से 15 से 20 प्रतिशत पानी की बचत होती है। इसके अलावा भूजल स्तर में 10 खेतों में चार-पांच सेमी पानी सुनिश्चित करने के लिए धान की फसल को लगभग दैनिक रूप से पानी देना पड़ता है। जब धान की पौध का तना विकास के चरण में होता है, तब अगले चार-पांच सप्ताह तक आम तौर पर किसान हर दो-तीन दिनों में खेत की सिंचाई

करते हैं। चूंकि धान की सीधी बुआई वाली डीएसआर तकनीक में पानी से भरे खेत की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होता है। इसके परिणामस्वरूप अगली फसल में उपज में वृद्धि होती है। चूंकि डीएसआर तकनीक में पानी और बेजली की भी बचत होती है, इसलिए वह किसानों के लिए कहीं करना भी शामिल है। एक आंकड़े के अनुसार 2020 में इस पद्धति से धान की खेती करने वाले किसान प्रति एकड़ लगभग 4,000 से 5,000 रुपये बचाने में कामयाब रहे। इससे लगभग 500 से 600 करोड़ रुपये की बचत हुई। पंजाब सरकार का लक्ष्य अब इस बचत को तीन गुना करना है। इसके लिए मान सरकार ने 12 लाख हेक्टेयर क्षेत्र

कर रहे हैं, लेकिन यह ध्यान रहे कि पंजाब के लिए डीएसआर तकनीक की सिफारिश 2010 में की गई थी। पता नहीं किंतु कारणों से पिछली सरकारों ने इसकी खबरियों से अवगत होने के बावजूद गत 12 वर्षों से इस तकनीक को बढ़ावा देने और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया? इसका परिणाम यह हुआ कि भूजल का स्तर और गिरता चला गया। कोविड महामारी ने डीएसआर को एक आशा की किरण के रूप में सामने लाने और पंजाब को अपने खोए हुए संसाधनों को पुनः प्राप्त करने का एक रास्ता दिखाया। डीएसआर तकनीक से होने वाले लाभ को देखते हुए ही पंजाब की आम आदमी पर्टी सरकार ने पिछली सरकारों की ऐतिहासिक गलती को सुधारने और धान की सीधी बुआई को प्रोत्साहित करने का फैसला किया है। पंजाब के किसानों ने राज्य को भारत का अनन्त का कटोरा बनाने में बहुत योगदान दिया है। अब समय आ गया है कि कारगर सांवित हो चुकी डीएसआर तकनीक को सभी किसानों की ओर से सहर्ष अपनाया जाए, ताकि भूजल संरक्षण के संकल्प को हासिल किया जा सके। इसके लिए उद्यम की भावना का प्रदर्शन करना होगा। इससे ही राज्य फिर से हंसता-खेलता पंजाब बनेगा। वास्तव में आवश्यकता तो इस बात की है कि धान की खेती के मामले में डीएसआर तकनीक को अन्यत्र भी अपनाया जाए, क्योंकि देश के कई इलाकें ऐसे हैं, जहां भूजल का स्तर लगातार गिरता जा रहा है।



अनिश्चित वैश्विक परिदृश्य के कारण यह आवश्यक हो गया है कि महंगाई पर लगाम लगाई जाए

लगातार परेशान करती महंगाई के बीच शनिवार की शाम एक राहत भरी खबर आई। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाने का एलान किया, जिससे बेलगाम महंगाई पर कुछ लगाम लगाने की उमीद बंधी है। इससे जहां लोग का आवाजाही से जुड़ा खर्च घटेगा, वहीं आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई सस्ती होने से भी राहत मिलेगी। पिछले कुछ अर्से से प्रत्येक वर्ग पर महंगाई का असर दिखने लगा था। विशेषकर निमन्-आय वर्ग के लिए यह नासूर बनती जा रही वहीं चीन में कोविड के विस्फोट एवं उस पर काबू पाने की कड़ी नीति ने आर्थिक मोर्चे पर एक नया जोखिम उत्पन्न कर दिया है। भारत बड़े पैमाने पर कच्चे तेल, गैस के अलावा तमाम औद्योगिक जिंसों और खाद्य तेल जैसी वस्तुओं का आयात करता है तो उस पर इनका असर पड़ा? स्वाभाविक है। इसे आयातित महंगाई का नाम दिया जाता है। इसका आशय है आयात की जाने वाली वस्तुओं के कारण बढ़े वाली महंगाई। सामान्य परिस्थितियों में भारतीय महंगाई

समाधान यही है कि जहां भारत हाइड्रोकार्बन पर अपनी निर्भरता घटाए, वहीं अधिक से अधिक वस्तुओं का घरेलू उत्पादन करे। सरकार द्वारा हरित ऊज़ा पर जोर और सेमीकंटकर जैसे उदयोग की स्थापना के लिए प्रोत्साहन इस दिशा में स्थागितयोग्य है, लेकिन उनके अपेक्षित परिणाम आने में समय लगेगा। मौजूदा परिस्थितियों की बात करें तो पेट्रोल-डीजल पर कर की दर घटाने की बहुत ज्यादा गुंजाइश न होने के बावजूद सरकार को ऐसा करने के लिए विवश होना

को जोड़कर देखा जाए तो सरकार के राजकोषीय घाटे में बढ़ोतरी निश्चित है। ऐसी स्थिति में सरकार को या तो बढ़े खर्च की पूर्ति के लिए ऋण लेना होगा, जिससे अन्य व्यक्तियों के लिए वित्तीय संसाधन सीमित होंगे या फिर सरकार को अपने पूँजीगत व्यय में कटौती करनी होगी। यानी सरकार के लिए एक नरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई जैसी स्थिति है। इस मुश्किल माहोल में कुछ सकारात्मक पहलू भी है। जैसे अगर महाराष्ट्र बढ़ रही है तो उससे नामिनल जीडीपी में

हार्डवे यर, सेंग क्षेत्र और आटोमोबाइल उद्योग में सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है। देश का विदेशी मुद्रा भंडर भी इस समय करीब 600 अरब डालर के मजबूत स्तर पर दिखाई दे रहा है। आज भारत मैन्यूफैक्चरिंग के क्षेत्र में विदेशी निवेश के लिए एक पसंदीदा देश के रूप में तेजी से उभर रहा है। दुनिया भर में यह माना जा रहा है कि भारत सस्ती लागत के विनिर्माण में चीन को पीछे छोड़ सकता है। भारत में विनिर्माण उद्योग जितनी अधिक तरक्की



परिदृश्य में आयातित महंगाई का अनुपात करीब 28 से 30 प्रतिशत के दायरे में होता है, लेकिन इस समय यह 60 प्रतिशत से भी ऊपर है। यह स्थिति की गभीरता को दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि वैशिवक रुझान किस प्रकार भारत में महंगाई की आग को हवा दे रहे हैं। कीमतों पर असर डालने के अलावा ये आर्थिक गतिविधियों की धार कुंद करने पर भी आमादा हैं। जैसे चीन में कोविड के कारण लगे लाकडाउन से देसी कंप्यूटर हार्डवेयर, कंज्यूमर डियूरेबल्स और दूरसंचार क्षेत्र की आपूर्ति पर असर पड़ा है। भारत अपनी आवश्यकता का करीब 53 प्रतिशत कंप्यूटर हार्डवेयर, 52 प्रतिशत कंज्यूमर डियूरेबल्स और 43 प्रतिशत दूरसंचार उपकरण एवं उनके निर्माण में आवश्यक कल्पुर्ज चीन से आयात करता है। ऐसे में यदि यह गतिरोध लंबा चला तो मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। इस आयातित महंगाई का दीर्घकालिक पड़ा। दरअसल महंगाई नियंत्रण में मौद्रिक नीति के मर्चे पर भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत ब्याज दरों में बढ़ातरी की प्रक्रिया शुरू कर दी है और आगे भी उसने दरों में तेजी कायम रखने के संकेत दिए हैं। ऐसे में अब पूरा दारोमदार राजकोषीय नीति पर आ गया था कि सरकार अपने स्तर पर कोई कदम उठाए। पेटोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क की दरें घटाना इसी रणनीति का हिस्सा है। जल्द ही इसका असर देखने को मिलेगा, जब महंगाई के आंकड़े सामने आएंगे। फिर भी इसमें कुछ समय तो लगेगा। सरकार पर इस कटौती के असर को लेकर वित्त मंत्री ने स्वयं स्वीकार किया है कि इस कारण सरकारी खजाने पर करीब एक लाख करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा। इससे पहले सरकार उर्वरक सभिकी में दोगनी बढ़ातरी कर चुकी है। खाद्य सॉब्साईं पर भी उसका खर्च बढ़ा तय है। इन पहलओं

बढ़ोतरी होगी और उसी अनुपात में कर संग्रह में भी तेजी आएगी। कोविड के बाद आर्थिक गतिविधियों में भी खासी तेजी का रुख हौसला बढ़ाने वाला है। वहीं जीएसटी जैसे आर्थिक सूधार के सकारात्मक प्रभाव अब प्रत्यक्ष दिखने लगे हैं। मानसून पूरी तरह मेहरबान रह सकता है। ऐसे में यदि सरकार महंगाई पर काबू पाने में कामयाब रहती है तो आर्थिक वृद्धि की तस्वीर को बदरंग होने से बचाया जा सकता है। अनिश्चित वैश्विक परिदृश्य के कारण यह और भी आवश्यक हो गया है कि महंगाई पर लगाम लगाई जाए, क्योंकि उससे व्यापक राहत के आसार नहीं दिख रहे। पिछले दोनों प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि कोविड महामारी और वर्तमान वैश्विक संघर्षों के बीच अपनी नई प्रतिभाशाली पीढ़ी के बल पर भारत स्टार्टअप और साफ्टवेयर से लेकर अंतरिक्ष जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सामर्थ्यवान देश के रूप में उभर रही है, तब भारत तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था गाले देश के रूप में चिह्नित किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वृद्धि चालू वित्त वर्ष में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 6.4 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। यह कोई छोटी बात नहीं है कि वैश्विक मटी की चुनौतियों के बीच वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में रिकार्ड बढ़ोतरी हुई है। गणित्य एवं उद्योग मंत्रालय के मुताबिक भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 में 83.57 अरब डालर का रिकार्ड एफडीआई प्राप्त किया है। वहीं वित्त वर्ष 2020-21 में यह आँकड़ा 81.97 अरब डालर था। प्रमुख निवेशक देशों के मामले में सिंगापुर 27 प्रतिशत के साथ शीर्ष पर मौजूद है। इसके बाद अमेरिका 18 प्रतिशत के साथ दूसरे, जबकि मारीशस 16 प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर है। कंप्यटर साफ्टवेयर एवं

अवधारणा के तहत सरकार द्वारा सेज से अंतर्राष्ट्रीय बाजार और राष्ट्रीय बाजार के लिए विनिर्माण करने वाले उत्पादकों को विशेष सुविधाओं से नवाजा जाएगा। देश को सामर्थ्यवान बनाने में देश के कृषि क्षेत्र की भी अहम भूमिका है। कृषि मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार फसल वर्ष 2021-22 में देश में कुल खाद्यानन्द उत्पादन रिकार्ड 31.45 करोड़ टन होगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 37.7 लाख टन अधिक है। यद्यपि इस वर्ष गेहूं का उत्पादन 10.64 करोड़ टन होगा, जो कि पिछले साल के मुकाबले 31 लाख टन कम है, लेकिन धान, मोटे अनाज, दलहन और तिळहन का रिकार्ड उत्पादन होता दिखाई दे रहा है। ऐसे परिदृश्य से जहां महंगाई और गरीबी नियंत्रित रहेगी, वहीं कृषि नियंता से ज़रूरतमंद देशों की मदद करते हुए विदेशी मुद्रा की कमाई भी की जा सकेगी।

